Highlights of Press Briefing 08 October, 2020

Shri Pawan Khera, Spokesperson, AICC addressed media at AICC Hdqrs, today

श्री पवन खेड़ा ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा- केन्द्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 6 सालों में बार-बार ऐसे उदाहरण दिए हैं, जिससे ये स्पष्ट हो जाता है कि मोदी सरकार सिर्फ अपने कुछ चुनिंदा अमीर दोस्तों के लिए सत्ता में आई है और सिर्फ उसी के लिए वो सत्ता में रहना चाहती है। हवाई अड्डों से लेकर बंदरगाहों तक, टेलीकोम से जो हमारी नवरत्ना कंपनी हैं उन तक और यहाँ तक कि भारत का गौरव माने जाने वाली भारतीय रेल तक मोदी सरकार अपने दोस्तों पर लुटाने के लिए सदैव तत्पर दिखाई देती है, ever ready. यह सरकार भूल जाती है कि देश और देश के भीतर इन तमाम संस्थानों का निर्माण सिर्फ कुछ पूंजीपतियों ने नहीं किया है, इस देश को एक-एक ईंट जमा-जमा कर, सजा-सजा कर इसका निर्माण एक-एक भारतवासी की मेहनत, उसके खून और पसीने से हुआ है। जिस देश को हर देशवासी ने बनाया हो, उसे चंद अमीरों पर कोई लुटा रहा हो, चंद अमीरों के हाथ उसको कोई बेच रहा हो, ये देखकर बहुत ज्यादा दुख होता है, पीड़ा होती है, हमें भी होता है और आपको भी होता है।

आज मैं आपके सामने आया हूं, खनन क्षेत्र में एक बहुत बड़े घोटाले की ओर आपका ध्यान आकर्षित करने। 2014 से पहले लोह अयस्क, जो कच्चा लोहा होता है, जिसको अंग्रेजी में आयरन कहते हैं। उसका निर्यात सिर्फ एमएमटीसी (MMTC) कर सकती थी, सिर्फ एमएमपीसी को ही उसकी अनुमति थी और एमएमटीसी भी सिर्फ वो लोहा अयस्क निर्यात कर सकती थी, जिसमें 64 प्रतिशत लोहे का संकेन्द्रण या कंसंट्रेशन होता है। 64 प्रतिशत FE आपने और हमने जो बचपन में केमेस्ट्री और सब पढ़ा था, उसमे थोड़ा सा याद दिला दूं, तो जो कॉस्ट्रेशन जिसमें 64 प्रतिशत FE का होता है, सिर्फ उसको एमएमटीसी निर्यात कर सकती थी और एमएमटीसी में 89 प्रतिशत सरकार की हिस्सेदारी है, ये एक सरकारी कंपनी है। लौह अयस्क के निर्यात पर 30 प्रतिशत निर्यात शुल्क भी लगता था। यह इसलिए किया जाता था ताकि उम्दा स्तर का लोहा देश में ही रहे और देश के स्टील प्लांट के उपयोग में आए।

2014 में जब मोदी सरकार आई तो यह तमाम नियम कानून आनन फानन में बदल दिए गए। स्टील मंत्रालय ने सबसे पहले तो 64 प्रतिशत लौह संकेन्द्रण का नियम बदला और Kudremukh Iron Ore Company Limited (KIOCL) को चीन, ताइवान, दक्षिण कोरिया और जापान में लौह अयस्क निर्यात की अनुमति दी। इसके अलावा मंत्रालय ने नीति में एक और परिवर्तन करते हुए यह घोषणा की कि लौह अयस्क पर तो 30 प्रतिशत निर्यात शुल्क जारी रहेगे लेकिन अगर यह लौह अयस्क छर्रों के रूप में निर्यात किया जाए तो उस पर कोई निर्यात शुल्क लागू नहीं होगा। निर्यात करने की अनुमति KIOCL को प्राप्त थी लेकिन 2014 से अब तक कई निजी कंपनियों ने छर्रों के माध्यम से हिन्दूस्तान का लौह अयस्क निर्यात करना शुरू कर दिया। इस पर शुल्क के रूप में हजारों करोड़ रूपये की चोरी हुई ।

अनुमान यह है कि इन निजी कंपनियों ने 2014 से अब तक लगभग 40 हजार करोड़ रूपये का लौह अयस्क निर्यात किया है। स्मरण रहे इन कंपनियों के पास लौह अयस्क को निर्यात करने की अनुमति नहीं थी। निजी क्षेत्र की वह कंपनियों जिनके पास अपने उपयोग के लिए लौह अयस्क की खदानें थी, उन्होंने भी मौके का फायदा उठाते हुए स्टील मंत्रालय और केन्द्र सरकार की नाक के नीचे उम्दा लौह अयस्क का निर्यात छर्रों के माध्यम से किया।

ऐसा करने से न केवल भारत के बेशकीमती प्राकृतिक संसाधन को लुटाया गया बल्कि 12,000 करोड़ रूपये का निर्यात शुल्क भी चोरी किया गया। Foreign Trade (Development and Regulation) Act 1992 के तहत इन कंपनियों पर लौह अयस्क छर्रों के गैर कानूनी निर्यात पर 2 लाख करोड़ का जुर्माना बनता है।

10 सितंबर 2020 को कानून मंत्रालय ने पत्र (संलग्न) के माध्यम से यह स्पष्ट भी किया कि छर्रों के निर्यात की अनुमति KIOCL को है और उसके अलावा जितनी भी कंपनियों इस्तेमाल कर रहे हैं वह गैर कानूनी है। यह न केवल Foreign Trade (Development and Regulation) Act 1992 के तहत गैर कानूनी है बल्कि कस्टम एक्ट 1962 के तहत भी यह गंभीर अपराध माना जाता है।

हम केन्द्र सरकार से यह जानना चाहते हैं:

1. उच्च गुणवत्ता के लौह अयस्क, जिसमें 64 प्रतिशत से ज्यादा लोहे का संकेन्द्रण हो, के निर्यात की अनुमति क्यों दे दी गई ?

2. वह कौन सी कंपनियां हैं जिन्होंने 2014 से लेकर अब तक बिना अनुमति के लौह अयस्क का निर्यात किया ? उनके नाम सार्वजनिक किए जाए।

3. 2014 से लेकर अब तक क्या सरकार ने, क्या सरकार की किसी भी जांच एजेंसी ने लौह अयस्क के गैर कानूनी निर्यात को लेकर किसी भी निजी क्षेत्र की कंपनी की जांच की ?

4. केन्द्र सरकार ने अपने किसी मंत्री अथवा इससे संबंधित अधिकारी जिन्होंने यह गैर कानूनी निर्यात होने दिया पर क्या कार्यवाही हुई ?

5. इस 2 लाख करोड़ के घोटाले में देश के बेशकीमती प्राकृतिक संसाधनों की खुली लुट हुई है इसकी नैतिक जिम्मेदारी नरेन्द्र मोदी जी किस पर टालेंगें।

हम इन तमाम प्रश्नों के उत्तर सरकार से पूछते हैं।

Shri Pawan Khera said- The central government led by Prime Minister Modi has time and again openly exhibited its love for its corporate well-wishers. India's airports, our sea ports, our telecommunication PSU's, even our railways is being sold to these private friends of Mr Modi. The government has forgotten that India and all its

institutions are not built by the wealth of crony capitalists; our nation is built because of the hard work and the blood and sweat of the common citizen. What the nation built as one is being divided and sold. The government has once again violated all principles to help some private players in the mining industry.

The export of iron ore by India is met with a 30% export duty and prior to 2014, only Metals and Minerals Trading Corporation of India (MMTC) was allowed to export Iron ore. Even MMTC was only allowed to export iron ore with 64% concentration of Iron (Fe) any export that exceeded this cap the MMTC, in which the government has an 89% share, had to take permission from the Government of India. The export cap was placed on iron ore to insure that there is sufficient supply of high quality iron ore back home to facilitate the growth of indigenous steel plants.

After the Modi Government came to power in 2014, all these rules and laws were thrown out the window. In 2014, the Steel Ministry of India removed the 64% Fe concentration cap on iron ore and along with that gave Kudremukh Iron Ore Company Limited (KIOCL) the permission to export iron ore to countries like China, Taiwan, South Korea, Japan etc.

What officials in the ministry did in addition to this was that a policy was drawn up where it was decided that iron ore exports will continue to have a 30% duty on them; however if the same iron ore is made into pellets and exported as pellets then there would be no duty on these exports. Despite KIOCL being the only company that had permission to export iron ore , since 2014 several private firms have indulged in the export of iron ore pellets, escaping duty on these exports and earning immeasurable profits.

It is estimated that these private firms have exported iron ore worth Rs 40,000 crore since 2014 violating the law as they did not have the license to export the ore. However these private players, as expected, have not been reprimanded or questioned by the central government and continue to flourish by exporting iron ore pellets. Even private firms that had iron ore mines for personal consumption and use by seeing this opportunity and by being in collusion with ministry officials started exporting iron ore pellets, all this happened under the nose of the central government or in complete knowledge of the government.

The Corporate-Modi alliance since 2014 has harmed the country in different ways. This time, the government has allowed the theft of essential national resources. These resources are the backbone of economic growth but are now in the hands of selected private companies. By not paying the export duty

the private players have robbed the government of around ***12,000 Crore*** in duty fee. **Under the Foreign Trade Development and Regulation Act 1992, these private players are liable to a penalty of *2,00,000 crores*** for this gross illegality.

On the 10th of September 2020 the Ministry of Law and Justice has clearly specified that the permission to export iron ore pellets was only given to Kudremukh Iron Ore Company Limited (KIOCL). [Copy Enclosed] This is illegal not just under the Foreign Trade Development and Regulation Act (1992), but is also a serious offence under the Customs Act 1962.

This is a government that works not for the country, but for the benefit of a selected few, the recent farmer bills have proven this. The happenings in the Steel ministry and industry have serious consequences for the entire nation; therefore we demand that an investigation must be initiated to expose the corruption since 2014 and how officials in the Steel ministry allowed theft in broad daylight.

There are also a few questions that the central government needs to answer:

- Why was high quality iron ore with greater than 64% iron concentration allowed to be exported contrary to earlier practices?
- Which all private firms have exported iron ore without permission since 2014? A detailed list must be made public.
- Since 2014 has the government questioned any private entity regarding their illegal dealings vis a vis iron ore export?
- What action has been initiated, if any against the officials of the steel ministry who allowed illegal export to take place?
- Was the change in policy of removing export duty for iron ore pellets done in consultation with all stakeholders?

The people have lost trust in this government. Governance is not done by selling country's pride. This expose once again proves that for Mr Narendra Modi, it is corporate first and India last.

On a question about the mining scam issue, Shri Khera said- We have demanded that all the names of those private players, who have been caught indulging in this corrupt practice, be made public and obviously if a scam has been happening before 6 years, you cannot just blame one part, which is the corporate, of course, they did the scam, but, there is a government, which is an accountable government which has allowed this scam to happen. So, the buck has to stop somewhere. We want to know from Mr. Modi, since in this Government, every buck stops at him, because there is nobody else visible, so obviously the questions are to him, he has to come out clean now.

It is enough, six years, you cannot have a honeymoon period for six years, you keep hiding from questions, you keep running away from issues, this cannot be allowed. Therefore, we seek your help also to make this Government answerable, to ensure that the Government does not resort to headline management. If we focus on farmers, they will go to Hathras, if we focus on Hathras, they will go to somewhere else, this can't be allowed, focus on all these issues, that are important including farmers, including Hathras, including the mining scam.

एक प्रश्न पर कि कांग्रेस इसमें आगे क्या करेगी? श्री खेड़ा ने कहा कि जो भी रास्ता इसमें हमें सूझेगा, जो भी हमें लगेगा कि न्याय दिलाने में सक्षम जो भी रास्ता दिखेगा, उस रास्ते पर जाएंगे। फिलहाल हम आपके कोर्ट में आए हैं, आपके दरवाजे पर आए हैं।

On another question on the same issue, Shri Khera said- No!, That is for Mr. Dharmendra Pradhan, if he is allowed to speak, because in this Government, No ministers are allowed to speak about their own departments, they speak on somebody else's department. So, we want Mr. Narendra Modi to make this list public. We don't know, who are the private players, whoever these private players are, irrespective of who they are, let their names be made public.

On another question, Shri Khera said- First of all, I object to the use of word clampdown, just because a particular case needs the version, the statement of all the stake holders that could include in this case as you said, a journalist, does not mean that there is a clampdown. If tomorrow, I am seen to be or I am found to be aware of something, the investigating agencies would have every right and it would also be their duty to ask me, now asking me does not mean clamping down on me, there is a major difference between a straight, simple, legal, legitimate question and clamping down. So, there is no clamp down. Let's remove this word out of our vocabulary when it comes to the Congress Party please, because we are very clear, very sure of what are the laws of the land, how are they to be applied and we are absolutely sure how they should not be misused, so we never misuse laws.

On another question, Shri Khera said- So, if I said in any ongoing investigation, you need to find out more details, more facts from whoever is in this possession of those facts, obviously, there will be investigation, but, I can assure you, under our government, no misuse of any law on anyone will take place.

On another question that UP CM has alleged that opposition is doing politics on dead bodies, Shri Khera said- if I remember, right, a lot of you reported in August, 2016, BJP was in opposition in UP, Keshav Prasad Maurya was the President of the BJP, he along with Mahesh Sharma and

other leaders, visited Bulandshahr, because there was a horrible incident of a rape and death in Bulandshahr. This was August, 2016, the BJP was in opposition in 2016 in UP.

Did anyone say that you are doing politics on dead bodies, what kind of insensitive remarks is this coming from a Chief Minister, who claims to be religious, who claims to be spiritualistic, he should think before he speaks. Just as Keshav Prasad Maurya was following his dharma as an opposition leader, nobody asked him not to do that. As opposition, it's our duty to flag these horrible crimes, to lend our political voice to these crimes, what does this Government want, 'Vipaksh Mukt Bharat'?

क्या चाहती है ये सरकार कि इस देश से विपक्ष समाप्त हो जाए, कि वो जो कर रहे हों, उनको करने दिया जाए और कोई अगर आवाज उठाए तो उसे किसी षड़यंत्र का हिस्सा बता दिया जाए। ये मजाक बना कर रख दिया है लोकतंत्र का। जब आप विपक्ष में हैं, जिन राज्यों में आप आज भी विपक्ष में है, आप भी आवाज उठाते हैं, और नहीं उठाते तो आप अपना राजधर्म का निर्वाह नहीं कर रहे हैं। आप भी अपने राजधर्म का निर्वाह कीजिए, कौन रोक रहा है आपको। बार-बार हमें ये कहा जाता है, कि वहाँ ये हो रहा है, आपके राज्य में हो रहा है, अगर हो रहा है, तो आप आइए और देखिए जांच अगर नहीं दुरुस्त चल रही है, तो आप भी आवाज उठाइए, आपका ये हक है, आपका ये कर्तव्य है। तो ये कहना कि विपक्ष लाशों की राजनीति खेल रहा है, इससे घिनौना मजाक हाथरस की उस बेटी के साथ नहीं हो सकता, जो योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं।

Sd/-
(Dr. Vineet Punia)
Secretary
Communication Deptt,
AICC